

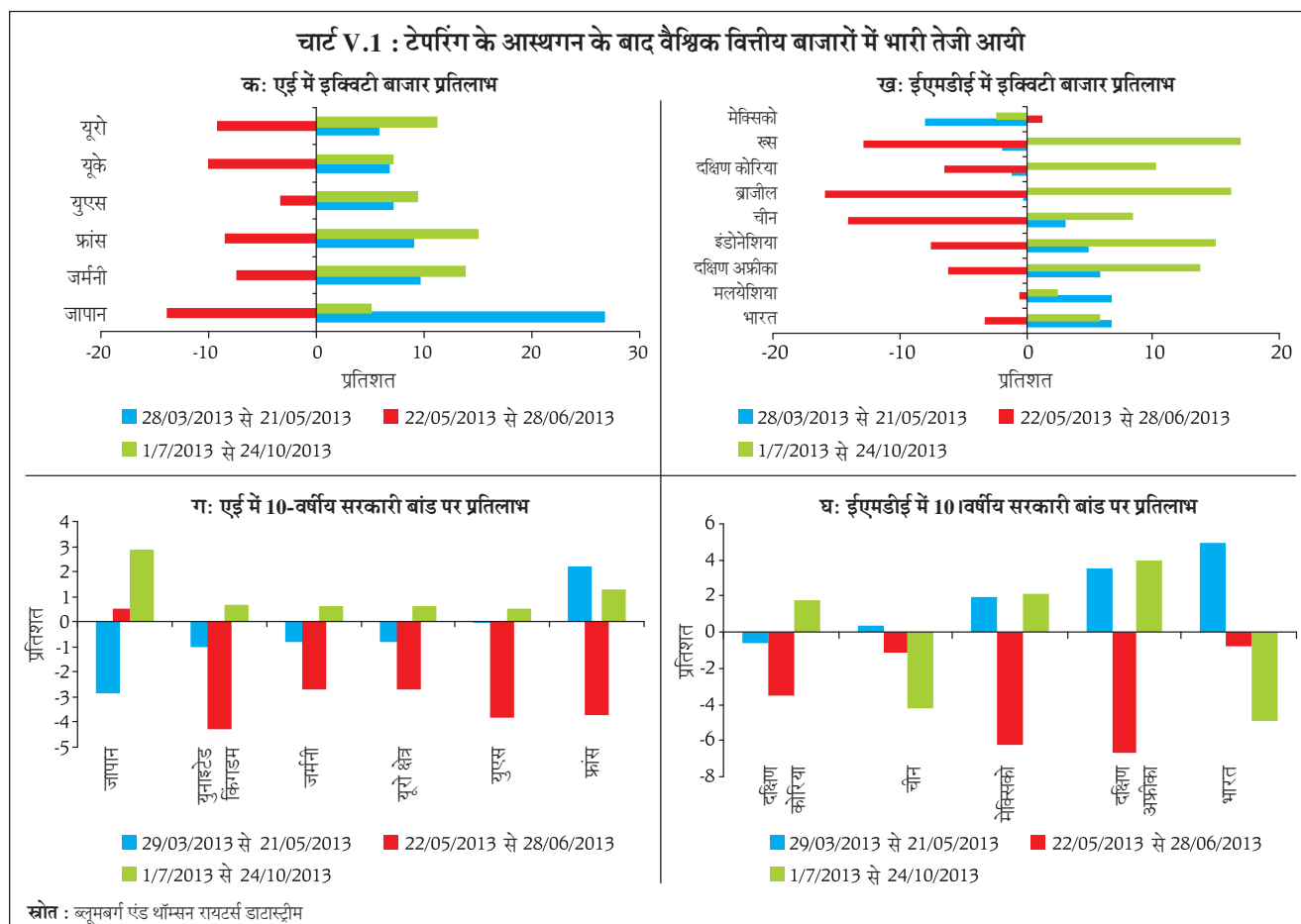
V. वित्तीय बाजार

युएस फेड द्वारा सितंबर 2013 में लिये गये इस निर्णय ने, कि यह बांड खरीद के अपने कार्यक्रम को जारी रखेगा, बाजारों को काफी शांत किया प्रतीत होता है। तब से, ईएमडीई के इक्विटी बाजारों और मुद्राओं में भारी तेजी आयी है। बांड बाजारों में भी दबाव कम हुए हैं। इन वैश्विक गतिविधियों पर और सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा की गयी नीतिगत कार्रवाई पर ध्यान देते हुए, भारतीय शेयर बाजार में पूर्वर्ती दो महीनों में मंदी रहने के बाद सितंबर 2013 में बदलाव आया। रुपये में भी सुधरे हुए व्यापार प्रवाह तथा इक्विटी अंतर्वाह की प्रतिक्रिया में मजबूती आयी। जबकि बाजारों को अस्थायी राहत मिली है, निकट भविष्य में अनिश्चितताएँ बनी हुई हैं और आकस्मिक जोखिमों का प्रबंध करने के लिए बफर बनाने के वास्ते कदम उठाये जाने की आवश्यकता होगी।

फेड की घोषणा निकट भविष्य में अनिश्चितता को कम करती है

V.1 यद्यपि इस समय यह कहना मुश्किल होगा कि ठीक-ठीक किस समय फेड अपने कार्यक्रम को क्रमशः समाप्त करना आरंभ करेगा, फिर भी यह स्पष्ट है कि बाजार के प्रतिभागी एक ऐसी दुनिया के लिए अपना समायोजन कर रहे हैं, जिसमें संभावित रूप से कम चलनिधि उपलब्ध होगी। फेड द्वारा 22 मई को दिये गये संकेत के बाद सभी देशों में इक्विटी, बांड और मुद्रा बाजारों और विशेष रूप से उभरते बाजारों ने काफी हानि होने का अनुभव क्या। कुछ मध्य-पूर्व देशों में अशांत भू-राजनीतिक वातावरण, जिसने कच्चा तेल मूल्य को बढ़ाया, ने विक्रय-जन्य दबावों को और उत्तेजित किया।

V.2 वर्ष 2013-14 की पहली छमाही में मध्य मई तक इक्विटियों में भारी तेजी का अनुभव हुआ था, जिसकी सहायता, अन्य बातों के साथ-साथ, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों की समंजनकारी मौद्रिक नीतियों ने की थी। अमेरिका के



बांडों में भी अप्रैल 2013 में भारी तेजी दिखाई पड़ी। तथापि क्यूई से निकास के बारे में फेड की घोषणा के चलते उन्नत और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई), दोनों में, इन जोखिमपूर्ण आस्तियों की कीमतों में भारी गिरावट देखी गयी (चार्ट V.1)।

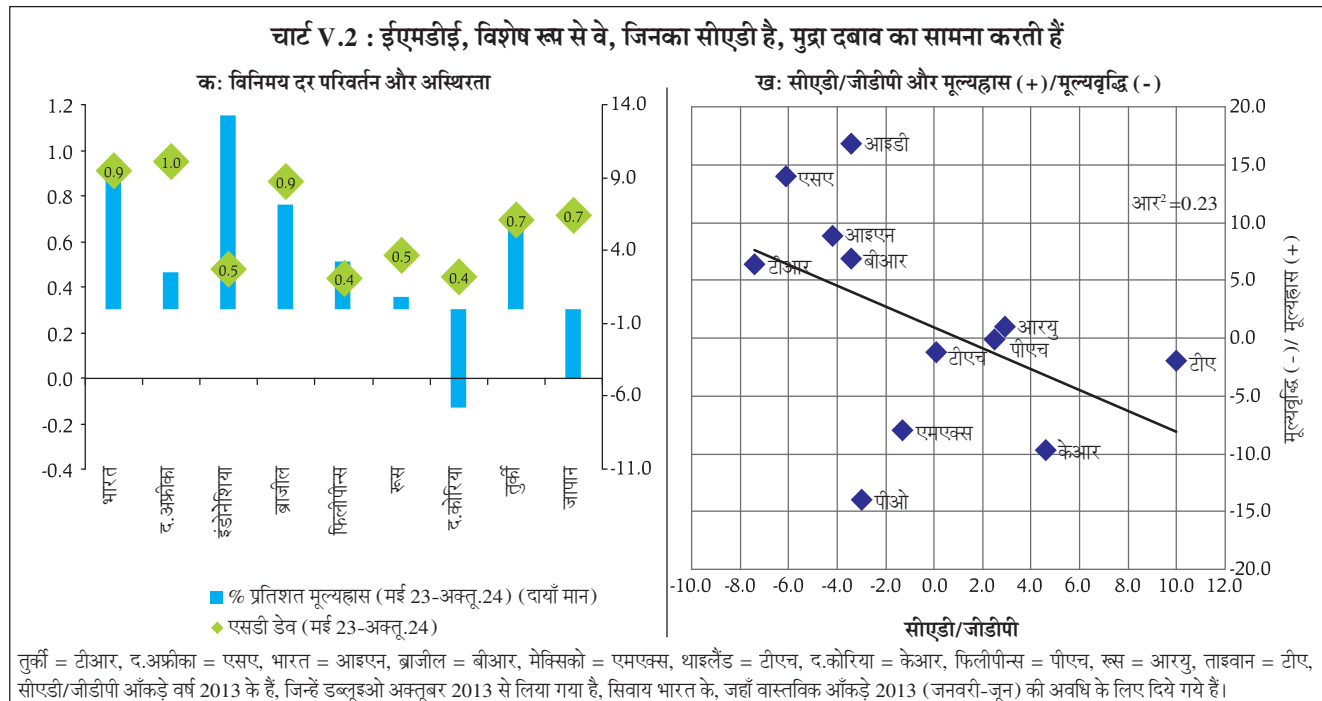
V.3 वर्ष 2013 की तीसरी तिमाही के आरंभ में वैश्विक वित्तीय बाजारों में फेड द्वारा क्यूई में क्रमशः कटौती किये जाने के समय को लेकर अटकल लगाये जाने की पृष्ठभूमि में अस्थिरता देखी गयी। सामान्यतः, ईएमडीई से पूँजी बहिर्वाह होने लगा, विशेष रूप से अमेरिका की ओर। इस प्रत्यावर्तन से उभरता बाजार बांड सूचकांक (इएमबीआई) स्प्रेड अंत-अगस्त में अचानक लगभग 375 आधार अंक तेज हो गया, जबकि फेड के टेपरिंग ऑफ वक्तव्य के अवसर पर यह लगभग 278 आधार अंक पर था; ईएमडीई के शेरों में गिरावट आयी और उनकी मुद्राओं में भी मूल्यहास हुआ। देश-विशिष्ट मुद्दे, यथा, चालू खाता में दुर्बलता, निर्यात वृद्धि का मंद होना, और संरचनात्मक बाधाओं ने उनकी चिंता बढ़ा दी।

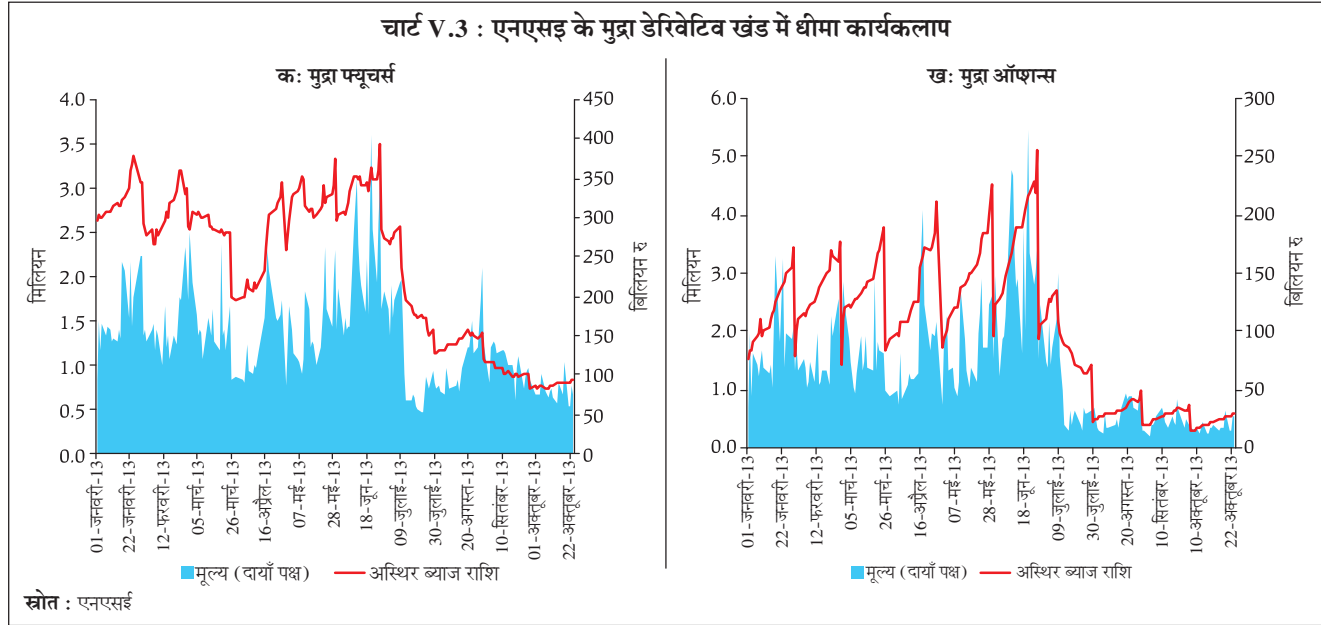
V.4 18 सितंबर को फेड के आस्ति-क्रय की मासिक प्रमात्रा को जारी रखने के निर्णय से, जिसमें कहा गया कि वे अपने कार्यक्रम का समायोजन करने के पूर्व यह देखेंगे कि आर्थिक पुनःप्राप्ति के टिके रहने का साक्ष्य मिलता है, बाजार के स्थान में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के इक्विटी

बाजारों में और ईएमडीई के इक्विटी बाजारों में उछाल आया, सरकारी बांड आय में नरमी आयी और अमरीकी डालर के विरुद्ध मुद्राओं में मूल्यवृद्धि हुई। यद्यपि 17 अक्टूबर को राजकोषीय सौदे पर हस्ताक्षर किये जाने से अमेरिका ऋणचूक करने से बचा, फिर भी चिंता बनी हुई है, क्योंकि इस सौदे से अमेरिकी सरकार को निधियाँ केवल 15 जनवरी 2014 तक प्राप्त होंगी और ऋण की अधिकतम सीमा 7 फरवरी 2014 तक बढ़ेगी। पुनः, खर्च-कटौती और हकदारी कार्यक्रमों के बारे में अगले कुछ महीनों में विवादास्पद बहस हो सकती है। अक्टूबर में अब तक (24 अक्टूबर 2013 तक) चुनिंदा ईएमडीई में इक्विटी बाजारों में औसतन 5.7 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गयी।

रुपये पर दबाव में कमी आयी लगती है

V.5 फेड की 'घोषणा के प्रभाव' के बाद स्थानीय मुद्राओं पर अधोमुखी दबाव के साथ काफी अस्थिरता सभी प्रमुख ईएमडीई में दृष्टिगोचर हुई। यह सीएडी वाले देशों और चालू खाता अधिशेष रखने वाले देशों, दोनों में पसर गयी। सीएडी वाले देशों में दक्षिण अफ्रीका, भारत और ब्राजील के मामले में अस्थिरता विशेष रूप से ऊँची थी। 28 अगस्त 2013 को प्रति डालर 68.36 के ऐतिहासिक न्यून स्तर पर पहुँचने के बाद नीतिगत उपक्रमणों की बाढ़ ने रुपये को लगभग 10 प्रतिशत तक पुनःप्राप्ति करने में (24 अक्टूबर 2013 को) समर्थ बनाया (चार्ट V.2)।





मुद्रा डेरिवेटिव कार्यकलाप में कमी आयी

V.6 बढ़ी हुई विनिमय दर अस्थिरता की पृष्ठभूमि में रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा घोषित विनियामक उपायों का प्रभाव डेरिवेटिव बाजारों पर स्पष्ट दिखाई पड़ा, जिनमें मुद्रा डेरिवेटिव में वर्ष 2013-14 की दूसरी तिमाही में गिरावट आयी (चार्ट V.3)।

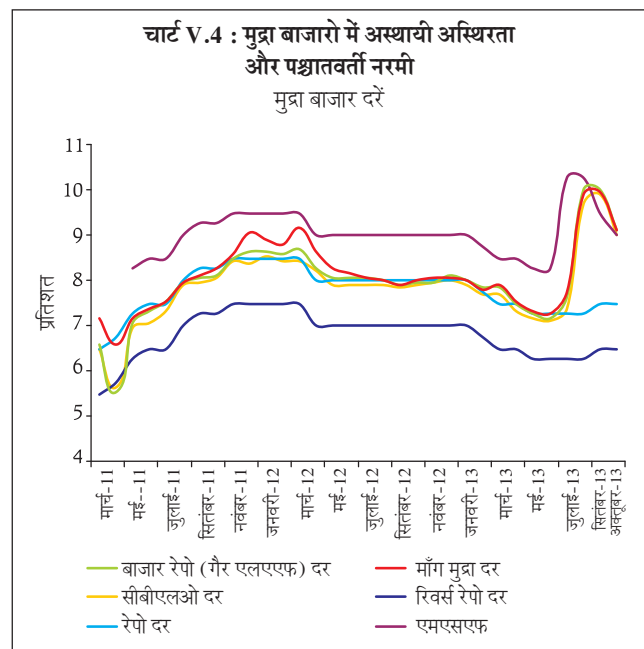
प्रारंभिक मुद्रा बाजार उथल-पुथल और पश्चातवर्ती नरमी

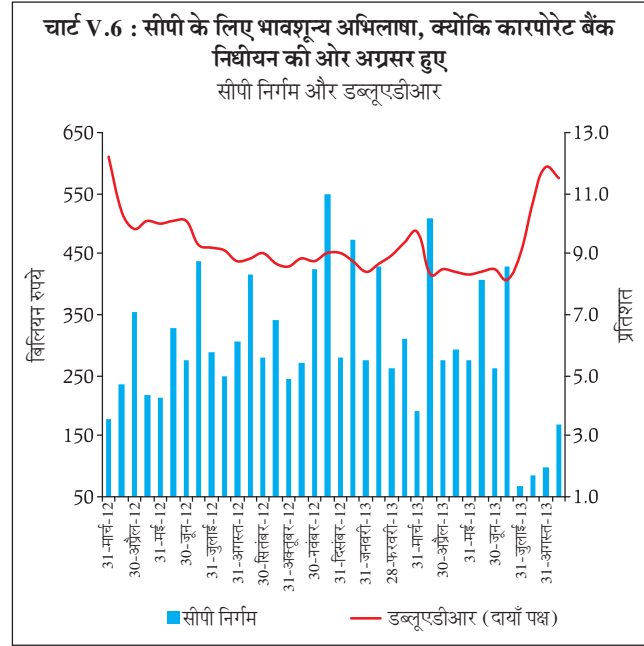
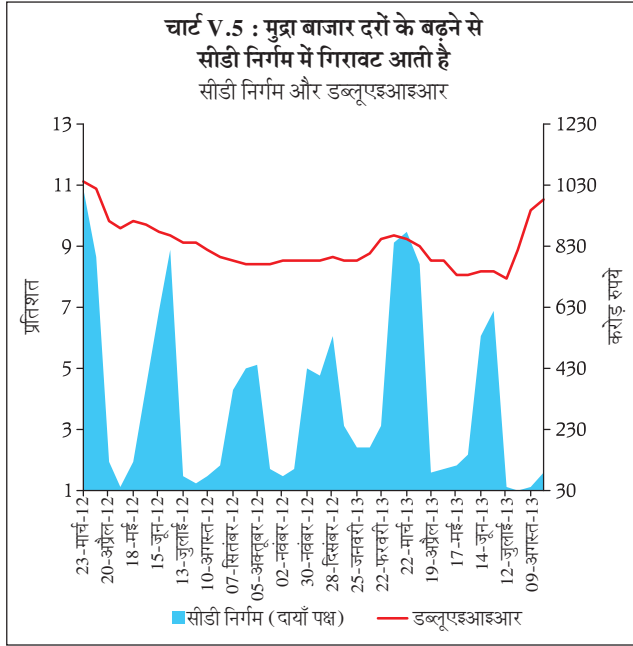
V.7 जुलाई 2013 के प्रथमाब्द में मुद्रा बाजार की स्थिति सहज थी। तथापि, रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई और अगस्त के दौरान किये गये अपवादात्मक उपायों ने मुद्रा बाजार को प्रभावित किया। भारत औसत माँग और सीबीएलओ दरें बढ़ कर सितंबर 2013 में क्रमशः 9.97 प्रतिशत और 9.90 प्रतिशत हो गयीं (चार्ट V.4)। अपवादात्मक उपायों को नपेतुले ढंग से वापस लेने की अपनी युक्ति के अनुक्रम में रिजर्व बैंक ने 7 अक्टूबर 2013 को एमएसएफ दर में 50 आधार अंक कटौती कर उसे 9.0 प्रतिशत कर दिया और 11 अक्टूबर 2013 से प्रत्येक शुक्रवार को परिवर्ती दर नीलामियों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली के एनडीटीएल की 0.25 प्रतिशत समतुल्य राशि के लिए 7-दिवसीय और 14-दिवसीय मीयादी रेपो के रूप में अतिरिक्त चलनिधि प्रदान करने के उपायों की घोषणा की। इसके परिणामस्वरूप, मुद्रा बाजार की दरें नरम हुईं, जिसमें

औसत माँग और सीबीएलओ दरें 25 अक्टूबर 2013 को क्रमशः 8.92 प्रतिशत और 8.97 प्रतिशत हो गयीं।

सीडी के निर्गम में गिरावट

V.8 चलनिधि को कठोर करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा किये गये उपायों ने इस खंड को प्रभावित किया लगता है, जिसमें सीडी की भारत औसत प्रभावी ब्याज दर (डब्ल्यूएडआईआर) बढ़ कर 6 सितंबर 2013 को 11.20 प्रतिशत हो गयी, जबकि अंत जून 2013 में यह 8.19 प्रतिशत थी (चार्ट V.5)। सीडी का औसत सकल पाक्षिक निर्गम घट कर वर्ष 2013-14 की





दूसरी तिमाही के दौरान 96 बिलियन रुपये हो गया (6 सितंबर 2013 तक), जबकि वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही के दौरान यह 340 बिलियन रुपये का हुआ था। सीडी की बकाया राशि भी घट कर 6 सितंबर 2013 को 3,011 बिलियन रुपये हो गयी, जबकि अंत-जून 2013 में यह 3,645 बिलियन रुपये थी।

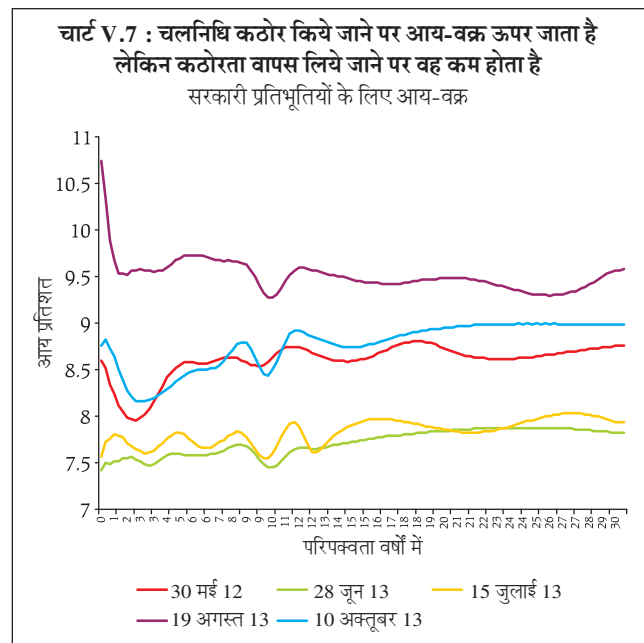
सीपी के लिए अभिलाषा में कमी आयी

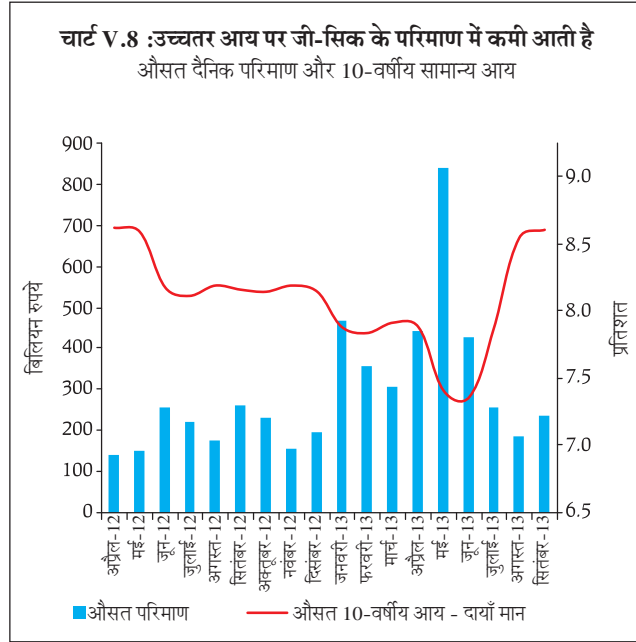
V.9 बढ़ा दरों में बढ़ोतरी होने के साथ सीपी निर्गम की अभिलाषा उल्लेखनीय रूप से कम हुई और कारपोरेटों द्वारा लिखत के माध्यम से निधीयन किये जाने के स्थान पर वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोतों से, विशेष रूप से बैंक ऋण के माध्यम से निधीयन किया जा रहा है। सीपी की भारित औसत बढ़ा दर (डब्ल्यूएडीआर) 15 सितंबर 2013 को बढ़ कर 11.53 प्रतिशत हो गयी, जबकि अंत-जून 2013 में यह 8.54 प्रतिशत थी (चार्ट V.6)।

जी-सिक आय में नरमी आयी

V.10 22 मई 2013 को की गयी 'घोषणा के प्रभाव' और बाद में रिजर्व बैंक द्वारा किये गये उपायों ने जी-सिक आय में महत्वपूर्ण वृद्धि की अगुआई की। 10-वर्षीय जी-सिक पर सामान्य आय बढ़ कर 19 अगस्त 2013 को 9.27 प्रतिशत हो गयी, जिसके बाद 20 अगस्त 2013 को ओएमओ खरीद नीलामी की घोषणा किये जाने पर इसमें नरमी आयी। मध्य

तिमाही मौद्रिक नीति समाक्षा में रेपो दर बढ़ाये जाने के बाद आय में वृद्धि होकर 30 सितंबर 2013 को यह 8.83 प्रतिशत हो गयी (चार्ट V.7)। तथापि, बाजार में भारी तेजी आयी और रिजर्व बैंक द्वारा जब 30 सितंबर को 100 बिलियन रुपये की ओएमओ खरीद नीलामी की घोषणा की गयी और 7 अक्टूबर 2013 को एमएसएफ दर 50 अंक घटा कर 9.0 प्रतिशत किया गया, उसके बाद आय में नरमी आयी। 10-वर्षीय सामान्य जी-सिक आय 25 अक्टूबर 2013 को 8.65 प्रतिशत पर बंद हुई।





V.11 केंद्र सरकार प्रतिभूतियों का औसत दैनिक व्यापार परिमाण न्यून रहा (चार्ट V.8)।

बढ़ते आय वातावरण के बाजूद सरकार के लिए उधार की लागत में कमी आती है

V.12 वर्ष 2013-14 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से केंद्र सरकार का सकल बाजार उधार (21 अक्टूबर 2013 तक) 3,890 बिलियन रुपये (निवल उधार 3.143 बिलियन रुपये) का था, जबकि पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि के दौरान यह 4.090 बिलियन रुपये (निवल उधार 3.234 बिलियन रुपये) का था (सारणी V.1)। दिनांकित प्रतिभूतियों की भारत औसत परिपक्वता सुधर कर 14.40 वर्ष हुई। प्राथमिक नीलामियों में बेंचमार्क 10-वर्षीय आय में वर्ष 2013-14 के प्रारंभ में कमी आयी, और वह 21 मई 2013 को 7.16 प्रतिशत के न्यून स्तर पर आ गयी और कम बनी रही। 15 जुलाई 2013 के बाद चलनिधि कठोरता के चलते आय में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोतरी हुई। इसके बावजूद, अब तक उधार की भारत औसत लागत पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि की तुलना में काफी नीचे रही है। तथापि, 24 अक्टूबर 2013 तक अंतरण की प्रमात्रा बढ़ कर 163.76 बिलियन रुपये हो गयी, जबकि पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि में यह 18.28 बिलियन रुपये थी।

V.13 वर्ष 2013-14 के दौरान (24 अक्टूबर 2013 तक) 24 राज्यों ने सकल आधार पर 970 बिलियन रुपये की राशि

सारणी V.1: प्राथमिक निर्गम की भारत औसत आय में वर्ष 2013-14 में गिरावट आयी

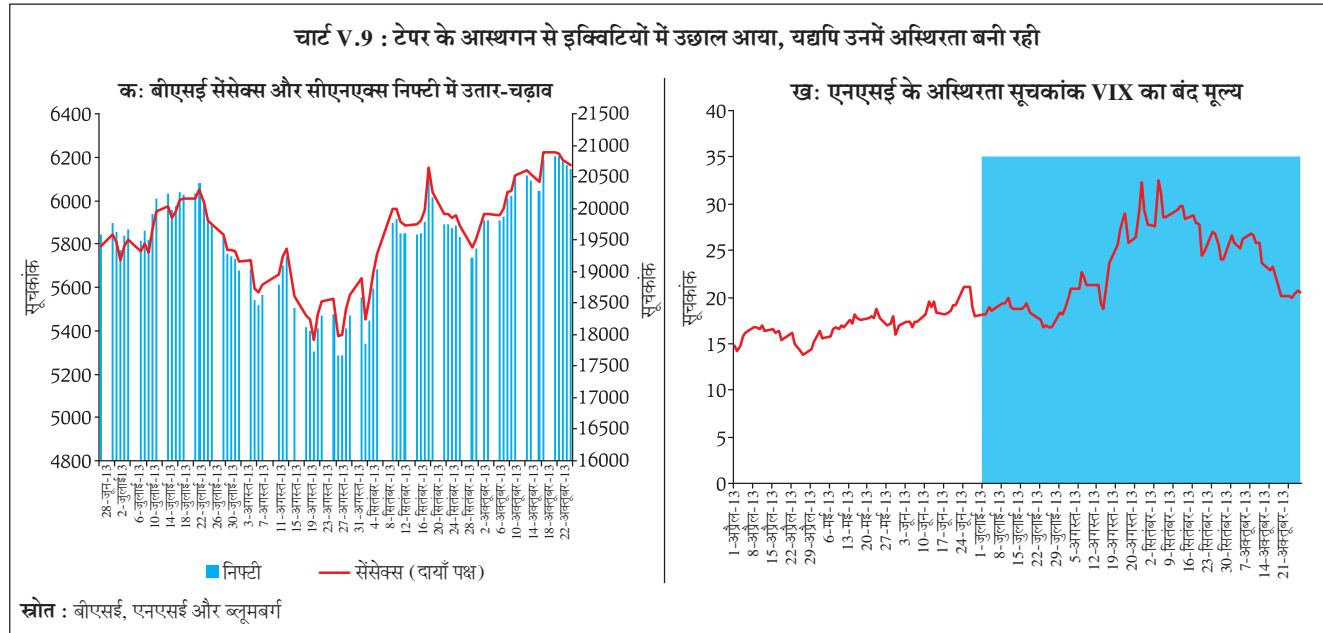
मद	2011-12	2012-13	2013-14*
1	2	3	4
केंद्र सरकार			
उगाही गयी सकल राशि (बिलियन रुपये)	5,100	5,580	3,890
बिड-कवर अनुपात (दायरा)	1.39-5.12	1.47-3.59	1.33-6.09
भारत औसत परिपक्वता (वर्ष)	12.66	13.52	14.40
भारत औसत प्रतिफल (प्रतिशत)	8.52	8.60	8.17
राज्य सरकार			
उगाही गयी सकल राशि (बिलियन रुपये)	1,586.3	1593.4	970
कट-ऑफ प्रतिफल दायरा (प्रतिशत)	8.36-9.49	8.67-9.31	7.57-9.94
भारत औसत प्रतिफल (प्रतिशत)	8.79	8.97	8.88

* 24 अक्टूबर 2013 तक।

जुटायी (निवल राशि 654 बिलियन रुपये), जबकि पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि में 25 राज्यों ने 966 बिलियन रुपये की राशि (निवल राशि 862 बिलियन रुपये) जुटायी थी। तदनुकूल अवधि में भारत औसत आय कम होकर 24 अक्टूबर 2013 को 8.88 प्रतिशत हो गयी, जबकि पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि में यह 8.93 प्रतिशत थी।

लाभ दर्ज करने के लिए इक्विटी बाजार उपायों और टेपर आस्थगन के प्रति प्रतिक्रिया दर्ज करता है

V.14 वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान (25 अक्टूबर 2013 तक) शेयर बाजारों में 9.8 प्रतिशत वृद्धि (सेंसेक्स में) और 8.1 प्रतिशत वृद्धि (निफ्टी में) दर्ज की गयी। तथापि, यह उतार-चढ़ाव इस अवधि में व्यापक परिभ्रमण को छिपाता है (चार्ट V9क)। प्रारंभिक लाभ के बाद 21 मई को की गयी घोषणा के प्रभाव के चलते विश्व के शेयर बाजारों ने गोता खाया। 22 मई और 30 अगस्त के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में क्रमशः 7 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की गिरावट आयी, क्योंकि एफआइआइ ने इस अवधि के दौरान घरेलू बाजारों में 13 बिलियन अमरीकी डालर का विनिवेश किया। तथापि, रिजर्व बैंक ने 4 सितंबर 2013 को बहुत सारे उपायों की घोषणा की, जिसके बाद इक्विटी बाजारों में पुनः प्राप्ति हुई। फेड द्वारा 18 सितंबर को की गयी घोषणा की सकारात्मक सुखद अनुभूति के प्रभाव ने भी बाजारों को बढ़ावा दिया। यह गति अक्टूबर में भी जारी रही, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी में 4 सितंबर 2013 की तुलना में क्रमशः 11 प्रतिशत और 13 प्रतिशत का लाभ 25 अक्टूबर 2013 तक दर्ज किया गया। बाजार में



भरोसा भी लौटा, जिसमें एफआईआई ने सितंबर-अक्तूबर के दौरान इक्विटी और ऋण खंडों में 1 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया (24 अक्तूबर 2013 तक)। इक्विटी बाजार की अस्थिरता, जिसका मापन एनएसई के VIX सूचकांक द्वारा किया जाता है, वर्ष 2013-14 की दूसरी तिमाही के दौरान बढ़ गयी (चार्ट V.9ख)।

प्राथमिक पूँजी बाजार निस्तेज बना रहा

V.15 वर्ष 2013-14 की पहली छमाही के दौरान लगभग 32 बिलियन रुपये की राशि 24 निर्गमों के माध्यम से प्राथमिक इक्विटी बाजार से जुटायी गयी थी। प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से संसाधन संग्रहण में तीव्र गति से गिरावट आयी। म्युचुअल फंडों द्वारा वर्ष 2013-14 की पहली छमाही के दौरान संसाधन संग्रहण में भी भारी कमी आयी, जिसका मुख्य कारण था, ऋण उन्मुख निधियों में दर्ज किया गया भारी प्रतिदान, विशेष रूप से जून-जुलाई और सितंबर 2013 के दौरान। एडीआर/जीडीआर के माध्यम से किये गये संसाधन संग्रहण में भी काफी गिरावट दर्ज की गयी (सारणी V.2)।

इक्विटी डेरिवेटिवों के खंड में पण्यवर्त में उछाल आया

V.16 अप्रैल-अगस्त 2013 के दौरान, इक्विटी डेरिवेटिव के खंड में पण्यवर्त 29.0 प्रतिशत बढ़ कर 206.7 ट्रिलियन रुपये का हो गया, जबकि पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि के दौरान यह 160.3 ट्रिलियन रुपये मूल्य का था। व्यापार परिमाण में भी

15.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह अप्रैल-अगस्त 2013 के दौरान 716.3 मिलियन संविदा का हुआ, जबकि अप्रैल-अगस्त 2012 में यह 621.1 मिलियन संविदा का हुआ था।

एनएसईएल के संकट ने प्रणालीगत संस्थाओं में विनियामक अंतराल को उजागर किया

V.17 उपभोक्ता कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा नैशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. (एनएसईएल) को दिये गये निदेशों

सारणी V.2: प्राथमिक पूँजी बाजार का संग्रहण निस्तेज बना रहा

(बिलियन रुपये)

कोटि	2012-13	2012-13	2013-14
	(अप्रैल-मार्च)	(अप्रैल-सितं.)	(अप्रैल-सितं.)
1	2	3	4
क. सार्वजनिक निर्गम (i) + (ii)	219.2	27.3	68.2
i) सार्वजनिक निर्गम (इक्विटी)	49.4	5.1	10.6
जिसमें: आइपीओ*	49.4	5.1	10.6
एफपीओ	0.0	0.0	0.0
ii) सार्वजनिक निर्गम (ऋण)	169.8	22.2	57.6
ख. राइट्स इश्यु	89.4	67.5	21.7
कुल इक्विटी निर्गम (i+ख)	138.8	72.6	32.2
ग. एडीआर/जीडीआर	10.4	9.9	1.2
घ. म्युचुअल फंड संग्रहण (निवल)	765.4	1018.7	353.4
i) निजी क्षेत्र	637.9	841.3	248.2
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	127.5	177.5	105.3
ड. कारपोरेट ऋण बाजार में प्राइवेट प्लेसमेंट	3614.6	1808.2	1428.2
च. क्यूआइपी	160.0	46.5#	52.0#

*: विक्रय प्रस्ताव शामिल नहीं है. #: अगस्त तक.

स्रोत : सेबी.

के परिणामस्वरूप एनएसइएल ने निर्णय लिया कि वह सभी संविदाओं का व्यापार निलंबित रखेगा, जिसमें इ-संविदाएँ शामिल हैं, और सभी एक-दिवसीय वायदा संविदाओं का निपटान फॉरवर्ड मार्केट कमीशन (एफएलसी) के पर्यवेक्षण में करेगा।

V.18 एनएसइएल के इस संकट ने वित्तीय संस्थाओं की अंतर्संबद्धता के मुद्दे को उठाया है। अनेक दलाली फर्में बहुविध खंडों में सक्रिय हैं, जिनमें इक्विटी, पण्य और विदेशी मुद्रा खंड शामिल हैं। उनके परिचालनों के एक खंड में हानि होने से उसका प्रसार अन्य खंडों में हो सकता है, जो बदले में पूरे बाजार में संक्रामक प्रभाव डाल सकता है।

V.19 केंद्र सरकार ने विनियामक कमियों को दूर करने के लिए अनेक नीतिगत उपक्रमण किये हैं। इसने एफएमसी का नियंत्रण वित्त मंत्रालय को अंतरित कर दिया है और दो समितियों का गठन किया है, जिनमें से एक के अध्यक्ष हैं आरबीआई के उप गवर्नर डॉ.के.सी.चक्रवर्ती और दूसरी के अध्यक्ष हैं आर्थिक कार्य मंत्रालय के अवर सचिव श्री अरविंद मायाराम। ये समितियाँ इस संकट से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जाँच-पड़ताल करेंगी। इन समितियों ने केंद्र सरकार को अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही में आवास कीमत में बढ़ोतरी कम हुई

V.20 अखिल भारतीय स्तर पर रिजर्व बैंक आवास मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष : 2010-11) में क्यू-ओ-क्यू वृद्धि वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही (नवीनतम उपलब्ध तिमाही) में 0.89 प्रतिशत पर कम थी, जबकि पिछली तिमाही में यह 2.46 प्रतिशत पर थी। बढ़ोतरी सबसे अधिक लखनऊ में देखी गयी, जिसके बाद अहमदाबाद और कोच्चि का स्थान है (सारणी V.3)।

सारणी V.3: नगर-विशिष्ट घट-बढ़ के साथ
आवास मूल्य वृद्धि में नरमी आयी

नगर	क्यू-ओ-क्यू (ति1 2013-14)	क्यू-ओ-क्यू (ति4 2012-13)	वाइ-ओ-वाइ (ति1 2013-14)	वाइ-ओ-वाइ (2012-13)
1	2	3	4	5
अहमदाबाद	4.47	2.90	15.05	11.87
बंगलूर	0.23	0.54	6.70	12.76
चेन्नै*	0.61	-0.09	15.98	18.95
दिल्ली	0.79	6.18	21.15	41.66
जयपुर	0.00	8.78	14.10	10.71
कानपुर	-9.35	-2.11	-28.00	-7.08
कोच्चि	2.28	-8.98	28.55	14.13
कोलकाता	1.42	4.25	27.06	47.66
लखनऊ	4.66	-1.82	27.56	25.06
मुंबई	0.28	0.36	8.38	18.15
अखिल भारत #	0.89	2.46	13.75	22.73

*: सूचकांक आवासीय और वाणिज्यिक, दोनों प्रकार की संपत्तियों पर आधारित है

#: सूचकांक भारत औसत नगर सूचकांक है, भारांक आबादी के अनुपात पर आधारित है।

निकट भविष्य की अनिश्चितताएँ चिरकालिक चिंता बनी हुई हैं

V.21 फेड ने निर्णय लिया है कि वह अपने बांड कार्यक्रम को क्रमशः वापस लेना आरंभ करने के पूर्व अधिक विश्वासोत्पादक साक्ष्य के लिए प्रतीक्षा करेगा। इसने बाजार को बहु-प्रतीक्षित राहत प्रदान की है। तथापि, बाजार की अनिश्चितता इस तथ्य से जुड़ी हुई है कि किस प्रकार ऋण की अधिकतम सीमा के मुद्दे आनेवाले कई महीनों में हल हो सकेंगे और क्या पुनःप्राप्ति के आरंभिक संकेत यूरो क्षेत्र में बने रहेंगे। भारत के बाजार भी घरेलू अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, जो दीर्घकालिक गिरावट, गिरते कारपोरेट उपार्जन और बढ़ते नियंत्रण से उत्पन्न हुई हैं, और इसके अतिरिक्त उन राजनीतिक अनिश्चितताओं की जोखिम का सामना वे कर रहे हैं, जो निर्वाचन चक्र से जुड़ी है।